पड़ता है।

अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के तरीके (Methods to Get maximum Social Advantage)

राज्य सरकार किसी भी अर्थव्यवस्था में अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए तीन मूलभूत सिद्धान्तों की सहायता ले सकती है। यह सिद्धान्त हैं :

1. सार्वजनिक व्यय उस स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए जहां राज्य द्वारा खर्च राशि की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाला लाभ सरकार द्वारा एकत्रित किये जाने वाले राजस्व के लिए किए गए त्याग की इकाई के बराबर हो।
2. राज्य के साधन व्यय की विभिन्न मदों में ऐसे वितरित किये जाएं कि प्रत्येक मद से प्राप्त होने वाली सीमांत संतुष्टि बराबर हो।
3. कर भी इस प्रकार से वितरित किए जाएं कि सभी कर दाताओं द्वारा कर के रूप में दिए गए धन की सीमांत उपयोगिता बराबर हो। राजस्व व व्यय का अनुकूलतम आबंटन हो।

सिद्धान्त की सीमाएं (Limitations of the Principle)

हम इस तर्क से सहमत हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त राज्य की वित्तीय गतिविधियों में सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। तिस पर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो कि व्यावहारिक जीवन में दिखाई देती है। ये सीमाएं निम्नलिखित हैं—

1. व्यवहार में लाना कठिन (Difficult to put into Practice) – अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसे व्यवहार में लाना अत्यन्त कठिन है। उपयोगिता के व्यक्तिपरक होने के कारण राज्य के समक्ष व्यय की सीमांत उपयोगिता को संतुलित करने में बहुत कठिनाई आती है। यहां एक ज्वलंत प्रश्न पैदा होता है कि सीमांत उपयोगिताओं व अनुपयोगिताओं को समाज के सदस्यों के बीच किस प्रकार विभाजित किया जाए। यह समस्या इस तथ्य के कारण और बढ़ जाती है कि कर संग्रहण तथा वास्तविक व्यय विभिन्न स्थानों पर अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जब भविष्य के किसी लाभ के लिए व्यय किया जाता है तो वर्तमान में उसकी उपयोगिता को मापना अनिश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए जब एक रेलवे लाइन के लिए एक पुल का निर्माण किया जाता है तो उसकी उपयोगिता अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग-अलग समय पर अलग-अलग सकती है। कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति एक रुपया देने के लिए तैयार हो सकता है तथा कोई अन्य व्यक्ति एक पैसा देने के लिए भी तैयार न हो। इन परिस्थितियों में परस्पर विरोधी विचारों पर एक साथ कैसे विचार किया जा सकता है ?

2. उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता (Utility is not Measurable) – इस सिद्धान्त की एक अन्य सीमा यह है कि उपयोगिता का परिमाणात्मक मापन नहीं जा सकता। अगर हम क्रमागत उपयोगिता के नियम को मानते हैं तो मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं। यह कैसे निर्णय किया जायें कि शिक्षा पर खर्च किया गया एक अतिरिक्त रुपया, सिंचाई पर खर्च किये गये एक अतिरिक्त रुपये से अधिक लाभदायक होगा ? क्या आयात शुल्क लगा कर प्राप्त किया गया एक अतिरिक्त रुपया उत्पादन शुल्क लगा कर प्राप्त किये गये एक रुपये से कम बोझिल होगा ?

3. बृहत व्यवस्था को भूलना (It ignores Macro System) – आलोचकों का कहना है कि कराधान से करदाताओं के लिए उत्पन्न होने वाली अनुपयोगिता की स्थिति बहुत छोटी-सी समस्या है जबकि यह धारणा समाज की व्यापक व्यवस्था की ओर ध्यान नहीं देती। इसी प्रकार कराधान के सीमांत त्याग को सार्वजनिक व्यय के सीमांत सामाजिक लाभ से समन्वित करने में बहुत बड़ी व्यवस्थागत व गंभीर असंगति आती है।

4. सीमित विषय क्षेत्र (Limited Scope) – **प्रो. डाल्टन** ने कहा है कि यह सिद्धान्त इस सामान्य धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक कर समाज के लिए बोझ है तथा सभी राज्य व्यय कल्याणकारी हैं। नशीली वस्तुओं के उपभोग पर लगाये जाने वाले कर को समाज पर बोझ नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार यदि राज्य सामाजिक मदों व अन्य जन सुविधाओं

Scanned with CamScanner

पर व्यय करता है तो यह बाह्य बचत का कारण बनता है। इसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता बढ़ जाती है। जिससे अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है परन्तु व्यवहार में सार्वजनिक व्यय का अधिकांश भाग आर्थिक कारणों की बजाय राजनीतिक दबाव में भी खर्च किया जाता है। इससे राज्य के सामाजिक कार्यों पर होने वाला व्यय प्रभावित होता है।

5. परिणामों का अनुमान लगाना कठिन (Difficult to forecast Result) – समाज की आधुनिक जटिलताओं के कारण किसी भी राज्य द्वारा अपनाए गए उपायों के परिणामों का अनुमान लगाना कठिन होता है। आसानी से यह अनुमान लगाना कठिन है कि दीर्घकाल में समाज की व्यवस्था किस सीमा तक उपभोग, उत्पादन, बचत व निवेश की से प्रभावित होगी। अतः कराधान व सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में सरकार के वित्तीय कार्यों के प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन है। इसके अतिरिक्त बजटीय नीति के प्रभाव एक विशेष अवधि तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए एक विशेष बजट वर्ष के संदर्भ में त्याग व कल्याण की चर्चा करना सही नहीं होगा।

6. अधिकतम सामाजिक कल्याण पर प्रतिबंध नहीं (No restriction on Maximum Social Advantage) – अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धान्त पर कोई प्रतिबंध नहीं है वरन् यह एक सहज प्रक्रिया है। वास्तव में सार्वजनिक आय व व्यय का अनुकूलतम आकार राष्ट्रीय आय के आकार के अनुरूप बदलता रहता है जो कि राज्य की वित्तीय क्रियाओं द्वारा निर्धारित होती है। राष्ट्रीय आय एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इसलिए अधिकतम सामाजिक कल्याण का निश्चित अनुमान लगाना कठिन है।

7. अत्यन्त अव्यावहारिक प्रतिबंध (Highly Unrealistic Restrictions) – यह तर्क देना कि, "**सरकार के बजट में आधिक्य या घाटा नहीं होना चाहिए**" यह अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने की दिशा में अत्यन्त आपत्तिजनक प्रतिबंध है। अल्पविकसित राष्ट्रों में जानबूझ कर घाटे की बजट नीति का पक्ष लिया जाता है ताकि आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सके। इसके विपरीत विकसित राष्ट्रों में उतार-चढ़ावों को कम करने के लिए प्रति चक्रीय (Contra Cyclical) बजट नीति अपनाई जाती है। यह प्रतिबंध अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावनाओं को हतोत्साहित करते हैं।

8. कल्याणकारी राज्य (Welfare State) – आधुनिक राज्य प्राचीन राज्यों की तरह पुलिस राज्य नहीं है। ये कल्याणकारी राज्य हैं जो सामाजिक-कल्याण के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य करते हैं। इस बारे में कोई असहमति नहीं है कि यह ऐसे दायित्व हैं जिन्हें पूरा करने में सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये व्यय है जैसे कि कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखना, लोगों को न्याय दिलाना, वृद्ध आय पेंशन देना, चिकित्सा सुविधाएं व आवासीय सुविधाएं देना। यदि किन्हीं परिस्थितियों में राज्य सरकार इन व्ययों को कम करना चाहे भी तो यह बहुत कठिन होता है।

सारांश (CONCLUSION)

सारांश में कहा जा सकता है कि कुछ सैद्धान्तिक व व्यावहारिक सीमाओं के अलावा अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धान्त सार्वजनिक वित्त को मापने के लिए उपयुक्त मापदण्ड प्रस्तुत करता है। यह राजस्व कार्यों के लाभ तथा लागत दोनों को ही देखता है तथा उनका समन्वय करने का प्रयास करता है। प्रो. डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिए कुछ वस्तुपरक परीक्षण सुझाए दिये हैं। आज के युग में सामान्य तौर पर सार्वजनिक नीति तथा विशेष रूप से राजकोषीय नीति से संबंधित ये उद्देश्य सभी राष्ट्रों से ही संबंधित हैं। पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। इसके विपरीत यदि राजकोषीय नीति विभिन्न उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करने का उद्देश्य रखती है तो वह अपना महत्व खो देती है।

Scanned with CamScanner